(2021)07 आईएलआर ए 232

पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार

आपराधिक पक्ष

दिनांक: इलाहाबाद 15.07.2021

समक्ष

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1481/2021

अशोक गुप्ता **... पुनरीक्षणवादी**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य **... विपक्षीगण**

पुनरीक्षणवादी के अधिवक्ता: श्री चंद्रजीत, श्री बाबू लाल राम

विपक्षी के अधिवक्ता: अपर शासकीय अधिवक्ता

(ए) आपराधिक कानून – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 451 – कुछ मामलों में लंबित संपत्ति की हिरासत और निपटान के लिए आदेश, धारा 457 – संपत्ति की जब्ती पर पुलिस की प्रक्रिया, सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 – धारा 3/4 – संपत्ति की अभिरक्षा एवं निस्तारण के लिए आदेश पारित करने के लिए संहिता की धारा 451 के तहत न्यायालय की शक्ति लागू की जा सकती है, केवल जांच के दौरान या परीक्षण के चरण में – विवेचना से संबंधित कार्यवाही जांच या परीक्षण के दायरे में नहीं है – धारा 451 के तहत न्यायालय की शक्तियों को विवेचना के स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता है। (पैरा – 18)

आवेदक–पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुलिस द्वारा जब्त की गई राशि की रिहाई के लिए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष संहिता की धारा 451 के तहत दायर आवेदन – खारिज कर दिया गया – इसलिए पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

अभिनिर्धारित किया गया – वर्तमान मामले के तथ्यों में, मामला विवेचना के चरण में लंबित था और परीक्षण का चरण अभी तक नहीं पहुंचा था। इस प्रकार अवर न्यायालय ने सही कहा है कि चूंकि विवेचना लंबित थी,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

इसलिए संहिता की धारा 451 के तहत शक्तियों का उपयोग करके संपत्ति की अभिरक्षा या निस्तारण के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। (पैरा – 16,19)

आपराधिक पुनरीक्षण खारिज कर दिया गया। (ई–6)

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा निर्गत किया गया)

1. श्री बाबू लाल राम को पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्रजीत की तरफ से और सुश्री सुषमा सोनी, राज्य–विपक्षी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान संशोधन को मुकदमा अपराध संख्या 346/2020 सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 की धारा 3/4 के तहत, पुलिस स्टेशन फजलगंज, जिला कानपुर नगर से उत्पन्न आपराधिक विविध आवेदन संख्या 516/2021 (राज्य बनाम अशोक गुप्ता और अन्य) में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2021 के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के समक्ष लंबित है, जहां उन्होंने मामले के लंबित रहने के दौरान पुनरीक्षणवादी के पक्ष में राशि जारी करने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 19731 की धारा 451 के तहत पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया है।

3. मामले के रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि पुलिस द्वारा जब्त की गई राशि को जारी करने के लिए संहिता की धारा 451 के तहत आवेदक–पुनरीक्षणवादी द्वारा दिनांक 20.01.2021 का आवेदन दायर किया गया था। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने आवेदन पर विचार करते हुए रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखा है और माना है कि फर्द बरामदगी प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि आवेदक के कब्जे से बरामद राशि का उपयोग जुआ खेलने के उद्देश्य से किया गया था और चूंकि विवेचना लंबित थी, इसलिए राशि जारी करने के लिए कोई निर्देश जारी करना उचित नहीं था।

4. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मामले के तथ्यों और पुनरीक्षणवादी के बचाव का हवाला देते हुए उपरोक्त आदेश को चुनौती देने की मांग की है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षणवादी द्वारा उठाए जाने वाले विवाद तथ्य और साक्ष्य के मूल्यांकन के विवादित प्रश्नों से संबंधित होंगे, जिन्हें इस स्तर पर नहीं देखा जा सकता है। यह भी बताया गया है कि संहिता की धारा 451 के तहत संपत्ति की अभिरक्षा और निस्तारण के लिए आदेश केवल मुकदमे या जांच के लंबित रहने के दौरान ही मांगा जा सकता है, न कि जांच के स्तर पर।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

6. धारा 451 से 459 के तहत उपाय, जो संहिता के अध्याय XXXIV के अंतर्गत आती है, में संपत्ति के निस्तारण के बारे में विस्तृत प्रावधान हैं; (ए) जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, या (बी) जिसका उपयोग किसी अपराध को अंजाम देने के लिए किया गया प्रतीत होता है, या (सी) जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, या (डी) जो न्यायालय की हिरासत में है।

7. जांच के दौरान पुलिस द्वारा जब्त की गई संपत्ति के संबंध में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, जिसमें जांच या परीक्षण के लंबित रहने तक ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा और निस्तारण के लिए अंतरिम आदेश पारित करने और जांच या परीक्षण के समापन पर अंतिम आदेश देने के प्रावधान शामिल हैं।

8. धारा 451 न्यायालय को किसी भी जांच या परीक्षण के दौरान प्रस्तुत संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित आदेश पारित करने का अधिकार देती है और तेजी से क्षय की स्थिति में न्यायालय संपत्ति की बिक्री या अन्यथा निस्तारण का निर्देश दे सकता है। धारा 451 के तहत आवेदन न्यायालय में संपत्ति की प्रस्तुति पर जांच या परीक्षण के लंबित रहने के दौरान किया जा सकता है। धारा 452 न्यायालय को मुकदमे या जांच के समापन पर संपत्ति के निस्तारण का निर्देश देने की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए, धारा 451 को जांच या परीक्षण के लंबित रहने के दौरान लागू किया जा सकता है, जबकि धारा 452 जांच या परीक्षण की समाप्ति के बाद लागू होगी और दोनों प्रावधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग तब किया जाएगा जब संपत्ति न्यायालय की हिरासत में हो या न्यायालय के समक्ष पेश की गई हो। धारा 451 या 452 के तहत प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां मामला अभी भी जांच के चरण में है।

9. धारा 457 में प्रावधान है कि जब भी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा संपत्ति की जब्ती की सूचना संहिता के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट को दी जाती है, और ऐसी संपत्ति को किसी जांच या परीक्षण के दौरान आपराधिक न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को संपत्ति के निस्तारण या वितरण के बारे में उपयुक्त निर्देश देने का अधिकार है।

10. संहिता की धारा 451, जो विशेष रूप से विवाद से संबंधित है, निम्नानुसार है:

"451. **कुछ मामलों में मुकदमा लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और निस्तारण का आदेश।** जब किसी जांच या विचारण के दौरान किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष कोई संपत्ति पेश की जाती है , तो न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है जो वह जांच या परीक्षण के समापन तक ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए उपयुक्त समझता है, और, यदि संपत्ति तेजी से और प्राकृतिक क्षय के अधीन है, या यदि अन्यथा

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

ऐसा करना समीचीन है, न्यायालय, ऐसे साक्ष्यों को दर्ज करने के बाद, जैसा कि वह आवश्यक समझती है, इसे बेचने या अन्यथा निपटाने का आदेश दे सकती है।

स्पष्टीकरण– इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "संपत्ति" में शामिल हैं–

(ए) किसी भी प्रकार की संपत्ति या दस्तावेज जो न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है या जो इसकी हिरासत में है,

(बी) कोई संपत्ति जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जिसका उपयोग किसी अपराध को अंजाम देने के लिए किया गया प्रतीत होता है।

11. संहिता की धारा 2 (जी) और 2 (एच) के तहत "जांच" और "विवेचना" शब्द को क्रमशः परिभाषित किया गया है, और वे इस प्रकार हैं:

(जी) "विवेचना" का अर्थ किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा इस संहिता के तहत की गई सुनवाई के अलावा प्रत्येक जांच से है;

(एच) "जांच" में इस संहिता के तहत किसी पुलिस अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति (मजिस्ट्रेट के अलावा) द्वारा किए गए साक्ष्य एकत्र करने के लिए सभी कार्यवाहियां शामिल हैं, जो इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत हैं;

12. "विचारण" शब्द, हालांकि संहिता के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, आमतौर पर एक न्यायिक कार्यवाही को संदर्भित करने के लिए समझा जाता है जो आरोप विरचित होने के बाद शुरू होता है और दोषसिद्धि या बरी होने के साथ समाप्त होता है।

13. संहिता की धारा 451 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, जहां किसी भी संपत्ति को जांच या परीक्षण के दौरान किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, न्यायालय ऐसा आदेश दे सकती है जो वह मुकदमे के समापन तक ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए उपयुक्त समझे, और, यदि संपत्ति तेजी से और प्राकृतिक क्षय के अधीन है, या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, तो न्यायालय, ऐसे साक्ष्यों को दर्ज करने के बाद, जैसा कि वह आवश्यक समझती है, इसे बेचने या अन्यथा निपटाने का आदेश दे सकती है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

14. धारा 451 के स्पष्टीकरण के खंड (ए) के अनुसार, किसी भी प्रकार की संपत्ति जो या तो न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है या न्यायालय की अभिरक्षा में है, धारा के दायरे में होगी। धारा 451 तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि जांच या परीक्षण के दौरान संपत्ति को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाता है।

15. यह धारा न्यायालय को जांच या मुकदमे के दौरान पेश की गई संपत्ति के निस्तारण के लिए अंतरिम हिरासत का आदेश देने का अधिकार देती है। यह आदेश (i) पूछताछ या मुकदमे के दौरान न्यायालय के समक्ष पेश की गई संपत्ति और (ii) संपत्ति जिसके बारे में अपराध किया गया प्रतीत होता है या जिसका उपयोग किसी अपराध को अंजाम देने के लिए किया गया प्रतीत होता है, दोनों के संबंध में पारित किया जा सकता है।

16. वर्तमान मामले के तथ्यों में, मामला जांच के चरण में लंबित था और परीक्षण का चरण अभी तक नहीं पहुंचा था।

17. मामला सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है, और अधिनियम की योजना के अनुसार, मजिस्ट्रेट या अधिकृत अधिकारी को गेमिंग के सभी उपकरणों की खोज करने, जब्त करने और धन और धन की सुरक्षा और मूल्यवान वस्तुएं, जिनमें यथोचित रूप से संदेह है कि उनका उपयोग गेमिंग के प्रयोजन के लिए किया गया है या उपयोग किए जाने का इरादा है, जो उसमें पाए जाते हैं, को कब्जे में लेने का अधिकार है।

18. संहिता की धारा 451 के तहत संपत्ति की अभिरक्षा और निस्तारण के लिए आदेश पारित करने के लिए न्यायालय की शक्ति का उपयोग केवल जांच के दौरान या परीक्षण के चरण में किया जा सकता है। विवेचना से संबंधित कार्यवाही जांच या परीक्षण के दायरे में नहीं है और इसलिए धारा 451 के तहत न्यायालय की शक्तियों को विवेचना के स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता है।

19. नीचे दिए गए न्यायालय ने इस प्रकार सही अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि विवेचना लंबित थी, इसलिए संहिता की धारा 451 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपत्ति की अभिरक्षा और निस्तारण के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

20. पुनरीक्षणवादी के अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति पर विवाद करने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि पुनरीक्षणवादी को मुकदमे के दौरान उचित चरण में संपत्ति जारी करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की स्वतंत्रता हो सकती है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

21. अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई भौतिक त्रुटि या अवैधता नहीं बताई गई है, पुनरीक्षण खारिज कर दिया गया है।

22. हालांकि, यह पुनरीक्षणवादी को उचित स्तर पर संपत्ति की अभिरक्षा और निस्तारण के आदेश के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने से नहीं रोकेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"